

[شری عبدالغنی ڈار : سیکرٹری صاحب میرا جواب سنٹ
آف آرڈر بڑا اچھا ہے۔ کل جب لوک پال بل پر
بہت ہوری گئی تو شری کنڈرل گیسٹا نے ایک پریج
موش کرنا چاہا۔ اس میں انھوں نے یہ کہا کہ
ملک میں جو پریسیڈنٹ کا ڈیلیکس ہوتے جا رہے
ہے اس میں بڑے کنڈرل پر شر شاخ ہو رہے ہیں
ذرا میری عرض سن لیجئے (دیرواہان)

SHRI S. M. BANERJEE : I rise to a point of order. Are we discussing Shri Nijalingappa or Shri Sanjiva Reddy here ? What is the hon. Member discussing now ?

श्री अन्वुल गनी डार : इन्होंने कहा कि इस वक्त इस बिल पर बहस को पोस्टपोन किया जाय और उस मामले को लिया जाय क्योंकि इस में देश की बड़ी हानि हो रही है : उन को कहना यह था कि रशिया का जो रेडियो है मास्को वह बार-बार एक कैंडीडेट का जिक्र कर रहा है, गिरि के हक में प्रोपेगैंडा कर रहा है... (व्यवधान)

[شری عبدالغنی ڈار : انھوں نے کہا کہ اس وقت
اس بل پر بحث کو پوسٹپون کیا جائے اور اس
مصلحہ کو لیا جائے کیونکہ اس میں دیش کی بڑی
ہانی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ رسیا کا جو
ریڈیو ہے۔ ماسکو کا وہ بار بار ایک کنڈیڈیٹ
کا ذکر کر رہا ہے گری کے حق میں پروپاگینڈہ
کر رہا ہے۔ (دیرواہان)]

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए इस बात को। मेरे बारे में आप ने कहा कि दो बजे के बाद मैं नहीं आता है तो उसकी वजह यह है कि जब से मैं आया मैं बराबर आप लोगों के साथ मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार मीटिंगें हुई हैं, अपनी अपनी तरफ से आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और डिप्टी स्पीकर साहब हैं नहीं, आ जाय तो अच्छा है...

(व्यवधान)... वह बिल्कुल सही सलामत हैं और काम भी सब ठीक चल रहा है।

We shall now adjourn for lunch and meet again at 14.00 hours.

13.05 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

[Shri Vasudevan Nair in the Chair]

RE : ALLEGED DISCUSSION BY CABINET OF CONGRESS PARTY MATTERS

श्री जार्ज फरनेग्बीज (बम्बई-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। आज सुबह के तमाम खबरों में यह खबर छपकर आई है कि भारत की सरकार की काबिना में, कैबिनेट में कांग्रेस दल... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : If it is not a point of order, I take it that he wants to make a submission to the Chair.

श्री जार्ज फरनेग्बीज : मैं भारत के संविधान को लेकर प्रश्न उठाना चाहता हूँ—प्लाइंट आफ घाडरन कहिये लेकिन भारत के संविधान को लेकर मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ।... (व्यवधान)... कल भाग्य सरकार की काबिना में, कांग्रेस पार्टी में इस समय चल रहे झगड़ों को लेकर काफी बहस हुई—यह खबर आज के खबरों में आई है। टाइम्स आफ इण्डियन ने पहले पन्ने पर लिखा है

"Cabinet fails to solve the crisis : the Union Cabinet discussed this evening the the grave crisis facing the Congress but was unable to evolve a solution to prevent the split in the party."

और भी उसमें काफी लम्बी खबरें हैं, उनको पढ़कर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरा निवेदन यह है कि आप

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

संविधान के आर्टिकल 74 को देखिए ।... (व्यवधान)... आप लोग सुनिये, सरकार को दल की चीज न बनाइये ।... (व्यवधान)... आप आर्टिकल 74 (1) और 75 (1) को देखिए :

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : What is he saying ? There is no business before the House.

MR. CHAIRMAN : I shall dispose of it within a minute or two.

SHRI GEORGE FERNANDES : Article 74 says :

"There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advice the President in the exercise of his functions."

And article 75 says :

"75 : The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

The Ministers shall hold office during the pleasure of the President.

The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People."

SHRI RANDHIR SINGH : We are in a majority ; the Prime Minister carries the majority with her. What is the point of order ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आपकी मेजरिटी परसों माइनारिटी में हो जायेगी ।

MR. CHAIRMAN : Let him complete his submission.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : तो मेरा निवेदन यह है कि धारा 74 और 75 दोनों में यह बात बिल्कुल साफ है कि जो सरकार की काबिना है उसकी जिम्मेदारी भारत के शासन को चलाने की है, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने और उनकी मदद करने की जिम्मेदारी कैबिनेट की है और उनकी जो यह जिम्मेदारी है वह इस सदन के साथ बंधी हुई है ।

The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.

इस पार्लियामेंट के साथ उनकी जिम्मेदारी है, उनको अपना रिश्ता इसके साथ रखना चाहिए। लेकिन दल के भीतर के भगड़े को लेकर, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव के मामले को लेकर या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को लेकर कोई भगड़ा हो, जब उस भगड़े को बहस के लिए भारत की काबिना में लिया जाता है तो यह सीधे-सीधे संविधान को खत्म करने वाली बात हो जानी है। दल और सरकार, ये दोनों एक चीजें नहीं हैं। हिन्दुस्तान में इस समय की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें दल और सरकार दोनों एक होकर राज्य चलाने का काम करें। यहां दोनों में फर्क है।... (व्यवधान)... भारत की काबिना की जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉसिबिलिटी है वह इस सदन के प्रति है, कांग्रेस पार्टी के प्रति नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी के अन्दर के मामलों को लेकर काबिना में बहस की जाती है तो उस पर हमको एतराज है। हम चाहेंगे कि आप इस सरकार में और प्रधान मंत्री से कहें संविधान की हत्या होती है, संविधान भंग होता है, संविधान को तोड़ने का काम होता है। इसके बारे में वह यहां पर एक खुलासा करें।

अन्त में एक बात और कहनी है। एक बात को मैं मान सकता हूँ, किसी राजनीतिक दल के बारे में तभी बहस हो सकती है जिस कि आपने एक कानून पार किया राजनीतिक दलों पर बंदिश डालने वाला प्रीवेंशन ऑफ अनलाफुल ऐक्टिविटीज। और कोई अनलाफुल ऐक्टिविटीज में कांग्रेस फंसी हुई है तो काबिना में बहस हो सकती है। लेकिन अपनी पार्टी के अन्दरूनी भगड़ों पर काबिना में बहस करेंगे तो यह कैबिनेट मिस्टम की हत्या है। इसलिये आप सरकार से कहें कि वह इस बारे में खुलासा करें।

SHRI RANDHIR SINGH : He has not been able to understand the Constitution.

MR. CHAIRMAN : Then, I am going to allow him.

MR. CHAIRMAN : I am not called upon to give any ruling, because no point of order was raised. The hon. Member wanted to make a submission and he has made it. Does the Law Minister want to say anything ?

श्री राम सेवक यादव : घापने कहा कि अखबार की खबर है। तो मन्त्री जी यहां बैठे हैं आप उन से जानकारी कर लें अगर वही एक कारण है तो।

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : The report to which he has referred is not a correct report. The Cabinet did not discuss anything but certain politicians who happen to be members of the Cabinet may have discussed something.

14.13 hrs.

LOKPAL AND LOKAYUKTA BILL—(Contd.)

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : This is a very important Bill but in the form in which it has come, I am sorry to say that it is a sham make believe hypocritical attempt at controlling or curbing the improper activities of officials and Ministers. You know, Sir, that a controversy is raging in Kerala to which Shri Umanath had referred yesterday.

MR. CHAIRMAN : I am not called upon to give any ruling. There is no point of order raised in the House. The hon. Member made some submissions. Some report appeared in the morning.....

SHRI RANDHIR SINGH : He wants that something should come in the papers. His purpose has been served. Kindly do not allow irrelevant things to be discussed here.

The fact that this Bill excludes the Prime Minister gives an opening to the State Ministries to exclude the Chief Ministers, and the fact that it excludes Members of Parliament gives room for excluding MLA's also.

MR. CHAIRMAN : If the matter was so important and the hon. Member was so very serious about it, he could have given proper notice of it in the morning itself and asked for some discussion or debate on the matter so that other Members can express their views if it is such an important constitutional matter. Any way, the Chair is not called upon to give any verdict on it. After all, it is a newspaper report.

The entire trouble throughout the working of the administration is due to the MP's and MLA's who raise questions concerning their constituencies and the issues that they make out of them so much so that every Minister is hampered and victimised and every officer is victimised by the MP's and MLA's. We in the Opposition can shirk some of the unreasonable demands but the Congress Members are forced to do certain things and they sit tight on the head of the Ministers or the officers and due to a lot of pressure they will be forced to do something wrong. Then, who suffers ? It is the poor officer who suffers. The secretary will send it to the under-secretary and the latter in turn will send it to the supervisory head and that poor man will suffer. This is a very unjust attitude that Government are taking. I would, therefore, request Government to accept the amendment seeking to include the Prime Minister also within the scope of this Bill. You know the saying that Caesar's wife must be above reproach. So also,

श्री जार्ज फरेनेन्डो : इन पर बहस की जाय। आप बहस के लिये समय मुकर्रर कीजिये।

MR. CHAIRMAN : I am not prepared to give any time for discussion now.

SHRI RAM SEWAK YADAV rose.

MR. CHAIRMAN : Does the hon. Member want to say something on the same subject or some other subject ?

श्री राम सेवक यादव (बागबंकी) : आप ने कहा कि अखबार की खबर है...